

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	कार्तिक 03, बुधवार, १११के 1945-अक्टूबर 25, 2023 <i>Kartika 03, Wednesday, Saka 1945- October 25, 2023</i>	

**भाग-1(ख)**

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**सार्वजनिक निर्माण विभाग**

**(पी.पी.पी. डिवीजन)**

अनुपूरक अधिसूचना

**जयपुर, अक्टूबर 12, 2023**

**अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)**

**संख्या प. 7(656)एस.एच.ए/पी.पी.पी/2021-22/109 :-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार धरियावद-पारसोला-साबला (एस.एच.-91) सड़कको ई.पी.सी. माध्यम से 2 लेन/2 लेनमय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला प्रतापगढ़में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	प्रतापगढ़	धरियावद	भरकुण्डी
2	प्रतापगढ़	धरियावद	भूंगाभट

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारणहेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा “एटलस मेनेजमेंट कन्सलटेन्सी सर्विसेस (ए.एम.सी.एस.) प्राइवेट लिमिटेड, राँची” एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूपरिपोर्टकी प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी।तत्पश्चातप्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।

3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रियाकोइसअधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि सेपूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

**सम्पर्कसूत्र:-**

1. श्री संजय कुमार सिंह
2. श्री अमित कुमार सिंह

कार्यालय - एटलस मैनेजमेंट कन्सलटेन्सी सर्विसेस(ए.एम.सी.एस.) प्राइवेट लिमिटेड, राँची

वास्ते विक्रम श्रीवास्तव

114/ए, अशोकपुरम, विपरीत रोड नं. 4, अशोकनगर,

जिला - राँची, (झारखण्ड) - 834002.

फोन नं. 7541811212

फोन नं. 8294447409

ई-मेल:amcspl@rediffmail.com

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,

संयुक्त सचिव, (पथ),

सार्वजनिक निर्माण विभाग।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।